



दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಮತ | ಹಿಂದಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ | बेंगलूर और चेन्नई से एक साथ प्रकाशित



5 श्रमिक और उद्योगपति एक-दूसरे के पूरक हैं, न कि प्रतिस्पर्धी : योगी

6 अरुणाचली चाल है पाक के हक में चीन की बौखलाहट

7 'चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान' का हिस्सा बने आशुतोष राणा

फ़र्स्ट टेक

पंजाब में आईएसआई संचालित नशीले पदार्थ की तस्करी का भंडाफोड़

चंडीगढ़/भाषा। पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि उसने पाकिस्तान स्थित और आईएसआई नियंत्रित **85 किलो** नार्को-तरकरी माँझूल का भंडाफोड़ किया है और भारत में इससे संबंधित गतिविधियां चलाने वाले व्यक्ति को 85 किलोग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट के माध्यम से बताया, तत्पश्चात पुलिस ने आईएसआई नियंत्रित पाकिस्तान आधारित मादक पदार्थ तरकरी माँझूल का पर्दाफाश किया है, जिसे ब्रिटेन में रहने वाले मादक पदार्थ तरकर लल्ली द्वारा संचालित किया जा रहा था।

इजराइल ने यमन में दो बंदरगाहों पर हमला किया, गाजा में हमले तेज
देर अल-बलाह/एपी। इजराइल की सेना ने शुक्रवार को कहा कि उसने यमन में दो बंदरगाहों पर हमला किया। इसने कहा कि ये बंदरगाह हूती आतंकवादी समूह के नियंत्रण में थे। इसने दावा किया कि होदेदा और सालिफ बंदरगाहों का उपयोग हूती द्वारा हथियार ले जाने के लिए किया जाता था। किसी के हताहत होने की तत्काल कोई सूचना नहीं है।

बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर 'गयाजी' किया
पटना/भाषा। बिहार सरकार ने शुक्रवार को गया शहर का नाम बदलकर 'गयाजी' करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव (कैबिनेट सचिवालय) एस. सिद्धार्थ ने बताया कि यह निर्णय शहर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के कारण लिया गया है।

रिजर्व बैंक ने डॉयचे बैंक एजी, यस बैंक पर जुर्माना लगाया
मुंबई/भाषा। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि उसने कुछ नियामक मानदंडों का पालन न करने के लिए डॉयचे बैंक एजी, इंडिया और यस बैंक पर जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि डॉयचे बैंक एजी, इंडिया पर बैंकों में बड़े कर्ज को लेकर केंद्रीय रिपॉजिटरी बनाने से जुड़े कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

17-05-2025 | **18-05-2025**
सूर्योदय 6:38 बजे | **सूर्यास्त 5:53 बजे**

BSE 82,330.59 (-200.15)
NSE 25,019.80 (-42.30)

सोना 9,890 रु. (24 कैरेट) प्रति ग्राम
चांदी 97,673 रु. प्रति किलो

निशान मंडेला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com



केलाश मण्डेला, मो. 9828233434

फैंकशास्त्र

सारे ही जब फैंक रहे तो, कृत्य न यह बदनाम करें। फैंकशास्त्र के सभी अध्याता, मिल कर इसे प्रणाम करें। कैसे कितनी कब-कब फैंके, कुछ सूत्रों को आम करें। फिक ना जाए मूल्य सियासी, इस पर थोड़ा काम करें।

संस्कृत विद्वान रामभद्राचार्य ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान जगद्गुरु रामभद्राचार्य और मशहूर कवि-गीतकार गुलजार को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया। गुलजार के नाम से मशहूर सम्पूर्ण सिंह कालरा को हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए जाना जाता है और उन्हें इस दौर के बेहतरीन उर्दू शायरों में से एक माना जाता है। कवि-गीतकार गुलजार 'स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं' के कारण समारोह में शामिल नहीं हो सके। चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक 75 वर्षीय रामभद्राचार्य प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक नेता, शिक्षाविद और चार महाकाव्यों समेत 240 से अधिक पुस्तकों और ग्रंथों के लेखक हैं। संस्कृत विद्वान को पुरस्कार स्वरूप प्रशस्ति पत्र,



नकद पुरस्कार और वाग्देवी सरस्वती की एक कार्यय प्रतिष्ठा प्रदान की गई। पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने संस्कृत साहित्य और समाज के लिए रामभद्राचार्य के 'बहुआयामी योगदान' की सराहना की। उन्होंने कहा, 'रामभद्राचार्य जी ने उत्कृष्टता के प्रेरक दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और आपका योगदान बहुआयामी है। दृष्टि बाधित होने के बावजूद आपने अपनी दिव्य दृष्टि से साहित्य और समाज की असाधारण सेवा की है। आप एक सहज कवि हैं।' मुर्मू ने कहा, 'आपके द्वारा लिखा गया संस्कृत साहित्य विपुल और उत्कृष्ट है। आप दिव्य भाषा संस्कृत के असाधारण उपासक हैं। भारतीय परंपराओं के सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकारों में आपका विशेष स्थान है।' उन्होंने पाणिनि की 'अष्टाध्यायी' की व्याख्या के साथ-साथ 'ब्रह्मसूत्र', 'भगवद् गीता' और प्रमुख उपनिषदों पर उनकी टिप्पणियों के लिए उनकी सराहना की।

जब सभी को समान अवसर, न्याय मिलता है तभी संविधान सफल होता है : सिद्धरामय्या

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

उमाल (मंगलूरु)/भाषा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने कहा कि जब सभी को समान अवसर और न्याय मिलता है तभी संविधान सफल होता है, इसीलिए उनकी सरकार सभी जातियों और धर्मों के गरीबों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए कई जनकल्याणकारी कार्यक्रम लागू किए गए हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने



शुक्रवार को यहां उमाला स्थित संयद मंदी दरगाह के उर्स कार्यक्रम के दौरान एक सामाजिक सत्राव सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद उसे संबोधित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि तमाम आलोचनाओं के बावजूद उनकी सरकार गरीबों के उत्थान के लिए इन योजनाओं को जारी रखेगी। उन्होंने कहा, 'हमें विविधता में एकता देखनी चाहिए। हम सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। जब सभी को समान अवसर और न्याय मिलता है तभी संविधान सफल होता है। सरकार इसी रास्ते पर चल रही है।' इससे पहले मुख्यमंत्री ने दरगाह पर जियारत भी की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष यू.टी. खादर और उमाला के काजी कांथापुरम ए.पी. अब्बाकर मुस्लिमयार ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

तमिलनाडु प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा

पनीरसेल्वम हैं राजग का हिस्सा

मुदुरै (तमिलनाडु)/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तमिलनाडु इकाई के प्रमुख नैनार नागोथिरन ने शुक्रवार को कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का हिस्सा बने रहेंगे। पनीरसेल्वम को संतुष्ट करने के प्रयास में नागोथिरन ने कहा कि वह राजग के घटक बने रहेंगे। पनीरसेल्वम को उनके पूर्व सहयोगी एवं पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने अनाद्रमुक से निष्कासित कर दिया था।

नागोथिरन का यह बयान पनीरसेल्वम द्वारा इस बात पर खुले तौर पर अफसोस व्यक्त करने के एक दिन बाद आया है कि 11 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चेन्नई यात्रा के दौरान उन्हें भाजपा द्वारा आमंत्रित नहीं किया गया था, जब पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले अनाद्रमुक के साथ चुनावी संबंध की औपचारिक घोषणा की गयी थी। नागोथिरन ने यहां संवाददाताओं से कहा, 'यह (अमित शाह) एक अलग उद्देश्य से चेन्नई में थे और उन्होंने अनाद्रमुक के साथ चुनावी गठबंधन को अंतिम रूप दिया और इसकी घोषणा की।'



पाकिस्तान के साथ चार दिन तक चले सैन्य टकराव के दौरान

आकाशतीर ने पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन हमलों को विफल किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारत की रविवार निर्मित आकाशतीर वायु रक्षा नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग प्रणाली ने पाकिस्तान के साथ चार दिन तक चले सैन्य टकराव के दौरान ड्रोन और मिसाइलों सहित पाकिस्तानी हवाई हमलों को बेअसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि जहां पाकिस्तान आयातित एचव्यू-9 और एचव्यू-16 प्रणालियों पर निर्भर



था, जो भारतीय हमलों को रोकने में विफल रहें, वहीं आकाशतीर ने स्वचालित वायु रक्षा में भारत के दबदबे को प्रदर्शित किया। सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड



रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'ऑपरेशन सिंदूर' पर कहा

हमारी कार्रवाई तो बस एक 'ट्रेलर' थी, जरूरत पड़ने पर पूरी 'पिक्चर' दिखाएंगे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

भुज (गुजरात)/भाषा। भारत ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से पाकिस्तान को दी जाने वाली एक अरब डॉलर की सहायता पर शुक्रवार को पुनर्विचार करने का आग्रह किया और कहा कि इस्लामाबाद इस सहायता का इस्तेमाल आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए कर सकता है। गुजरात के भुज वायुसेना स्टेशन पर वायु योद्धाओं को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'ऑपरेशन सिंदूर' में 'ब्रह्मोस' सुपरसोनिक मिसाइल के इस्तेमाल की पुष्टि की और कहा कि इस हथियार ने पाकिस्तान को 'रात के अंधेरे में दिन का उजाला' दिखा दिया है।

आतंकवाद को समर्थन बंद करने तक पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी: जल शक्ति मंत्रालय

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने कैबिनेट सचिव को बताया है कि सिंधु जल संधि तब तक निलंबित रहेगी, 'जब तक पाकिस्तान विश्वसनीय और स्थायी रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता।' कैबिनेट सचिव टी.टी. सोमनाथन को मंगलवार को सौंपी अपनी मासिक रिपोर्ट में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय की सचिव देवाश्री मुखर्जी ने कहा कि सरकार ने घोषणा की है कि पहलगाम में नागरिकों पर 'पाकिस्तान प्रायोजित' आतंकवादी हमले के बाद संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। मुखर्जी ने अपनी रिपोर्ट में कहा, 'जब तक पाकिस्तान विश्वसनीय और स्थायी रूप से सीमा पार आतंकवाद को समर्थन करना नहीं छोड़ देता, तब तक प्रमुख जल-बंटवारा संधि निलंबित रहेगी।'

भारत नहीं चाहता कि वह जो धन आईएमएफ को देता है उसका इस्तेमाल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान या किसी अन्य देश में आतंकवादी बुनियादी ढांचा तैयार करने में किया जाए।

पाकिस्तान को स्पष्ट और कड़ा संदेश देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि मौजूदा 'संचर्षविराम' का मतलब है कि भारत ने पाकिस्तान को उसके बर्ताव के आधार पर 'परिचीक्षा' पर रखा है। उन्होंने कहा, 'यदि उसका बर्ताव सुधरता है, तब तो ठीक और यदि कोई गड़बड़ी करता है, तो उसे कड़ा दंड दिया जाएगा।' सिंह ने कहा, 'हमारी कार्रवाई तो बस एक ट्रेलर थी, अगर जरूरत पड़ी तो हम पूरी पिक्चर भी दिखाएंगे। आतंकवाद पर

हमला करना और उसे खत्म करना नये भारत का 'न्यू नॉर्मल' है।' 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत भारत ने सात मई की सुबह पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में नौ आतंकी ढांचे नष्ट कर दिए थे। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया गया जिसके बाद भारत की तरफ से की गयी जवाबी कार्रवाई में उसके कई सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा। चार दिन तक चले

टकराव के बाद 10 मई को दोनों पक्षों के बीच संघर्ष रोकने पर सहमति बनी थी।

अपने संबोधन में सिंह ने कहा कि पाकिस्तान पिछले सप्ताह भारत द्वारा नष्ट किए गए आतंकी ढांचे को फिर से खड़ा करने की कोशिश में लग गया है और इस्लामाबाद 'पाकिस्तान के आम नागरिकों से एकत्र की गई राशि को आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के आका और संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी मसूद अजहर को लगभग 14 करोड़ रुपये देने में खर्च करेगा।'

वायु सेना का यह अड्डा उन सैन्य बुनियादी ढांचे में से एक है जिसे पाकिस्तान ने चार दिन तक जारी सैन्य संघर्ष के दौरान निशाना बनाया था।

आर्थिक संकट से जूझ रही वोडाफोन आइडिया ने कहा

सरकारी समर्थन नहीं मिलने पर 2025-26 के आगे नहीं कर पाएंगे परिचालन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। आर्थिक संकट से जूझ रही वोडाफोन आइडिया ने दूरसंचार विभाग से कहा है कि समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया पर सरकार से समय पर समर्थन न मिलने की स्थिति में वह वित्त वर्ष 2025-26 से आगे परिचालन नहीं कर पाएगी।

वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) ने 17 अप्रैल, 2025 को दूरसंचार विभाग को भेजे एक पत्र में खुद को नई जीवन रेखा देने का अनुरोध करते हुए कहा, कोई समर्थन नहीं मिलने पर उसकी वापसी असंभव हो जाएगी।

वीआईएल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अक्षय मूंदड़ा ने दूरसंचार सचिव को लिखे पत्र में कहा, एजीआर पर भारत सरकार



का समय पर समर्थन मिले बगैर वीआईएल वित्त वर्ष 2025-26 से आगे परिचालन नहीं कर पाएगी क्योंकि बैंक से वित्तपोषण की चर्चाएं आगे नहीं बढ़ पाएंगी। वीआईएल में सबसे अधिक 49 प्रतिशत हिस्सेदारी सरकार के पास है। स्पेक्ट्रम शुल्क और एजीआर बकाया को इकट्ठी हिस्सेदारी में बदले जाने से सरकार इस कंपनी में सबसे बड़ी शेयरधारक बन चुकी है। उद्यतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को वोडाफोन आइडिया की एक नई याचिका की सुनवाई करने पर सहमति जताई जिसमें लगभग 30,000 करोड़ रुपये के एजीआर बकाया को माफ

करने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ से वीआईएल के वकील मुकुल रोहतगी ने आग्रह किया था कि याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है।

पीठ इस याचिका पर 19 मई को सुनवाई कर सकती है। वोडाफोन आइडिया ने पत्र में दूरसंचार विभाग को आगाह किया है कि बैंकों से ऋण न मिलने की स्थिति में वह निवेश की योजना पर आगे नहीं बढ़ पाएगी।

वीआईएल ने कहा, ऐसा होने पर परिचालन प्रदर्शन में सुधार रुक जाएगा। इसके साथ कंपनी द्वारा जुटाए गए कोष का जल्द ही उपयोग होगा और पूरा पूंजीगत व्यय चक्र थम जाएगा। ऐसी स्थिति में, पिछले 12 महीनों में जुटाए गए समूचे कोष और कंपनी द्वारा अब तक किए गए निवेश के साथ सरकारी हिस्सेदारी का मूल्य भी घट जाएगा।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री डार ने 'फर्जी' खबर का इस्तेमाल कर वायुसेना की प्रशंसा की



दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

इस्लामाबाद/भाषा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने संसद के ऊपरी सदन 'सिनेट' में अपने देश की वायु सेना की प्रशंसा करने के लिए एक 'फर्जी' खबर का सहारा लिया और इसे एक ब्रिटिश दैनिक की खबर बताया। डार ने 'फर्जी खबर' का हवाला देते हुए सांसदों को बताया

■ डार ने 'फर्जी खबर' का हवाला देते हुए सांसदों को बताया कि 'द डेली टेलीग्राफ' ने खबर दी है कि 'पाकिस्तानी वायुसेना ने आसमान में निर्विवाद बादशाहत कायम की है।'

■ उनके दावे की तथ्य-जांच हालांकि 'डॉन' अखबार ने की, जिसने इस खबर को 'फर्जी' करार दिया।

कि 'द डेली टेलीग्राफ' ने खबर दी है कि 'पाकिस्तानी वायुसेना ने आसमान में निर्विवाद बादशाहत कायम की है।' उनके दावे की तथ्य-जांच हालांकि 'डॉन' अखबार ने की, जिसने इस खबर को 'फर्जी' करार दिया।

अखबार ने कहा, 'सोशल मीडिया पर कई उपयोगकर्ताओं द्वारा 10 मई, 2025 से एक तस्वीर प्रसारित की जा रही है, जिसमें ब्रिटेन के 'द डेली टेलीग्राफ' अखबार के पहले पृष्ठ पर भारत के

साथ हाल में हुए संघर्ष के बीच पाकिस्तान वायु सेना को आसमान का बादशाह घोषित किया गया है। हालांकि, ऐसा कोई लेख प्रकाशित नहीं हुआ है और स्क्रीनशॉट फर्जी है।' इसमें कहा गया है कि बैरिस्टर खदीजा सिद्दीकी ने 10 मई को ब्रिटिश दैनिक के नाम से फर्जी खबर की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें एक समाचार के साथ एक शीर्षक था: 'पाकिस्तान वायु सेना: आसमान की निर्विवाद बादशाहत'।

ईजमाईट्रिप के संस्थापक ने मेकमाईट्रिप के बोर्ड सदस्यों के ‘चीन से संबंधों’ पर निशाना साधा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। यात्रा मंच ईजमाईट्रिप के संस्थापक और चेयरमैन निशांत पिड्डी ने शुक्रवार को प्रतिब्रद्धी मेकमाईट्रिप पर आरोप लगाया कि कंपनी के 10 में पांच निदेशकों का चीन से सीधा संबंध है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा है कि मेकमाईट्रिप की रणनीतिक रूप से चार सबसे महत्वपूर्ण बोर्ड समितियों में तीन ‘स्पष्ट रूप से चीनी संबंधों वाले निदेशकों के नेतृत्व में हैं या उनसे काफी प्रभावित हैं।’ दूसरी ओर मेकमाईट्रिप ने पिड्डी के आरोपों पर टिप्पणी करने से इनकार किया और भारतीय

विवादित टिप्पणी को लेकर मप्र के उपमुख्यमंत्री ने दी सफाई, कहा- बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जबलपुर/इंदौर/भाषा। मध्यप्रदेश के उपमुख्यमंत्री जादवीश देवड़ा ने सेना और सैनिकों को लेकर दिये गए कथित विवादित बयान पर शुक्रवार को सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। उपमुख्यमंत्री ने जबलपुर में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा था कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए देश, उसकी सेना और सैनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। अपने इस बयान को लेकर विवाद पैदा होने के

कैट ने पाकिस्तान को ‘समर्थन’ देने पर तुर्किये, अजरबैजान के बहिष्कार का किया आह्वान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (कैट) ने तुर्किये और अजरबैजान के साथ सभी व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंधों का बहिष्कार करने का शुक्रवार को फैसला किया। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत द्वारा चलाए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर पाकिस्तान का ‘समर्थन’ करने के लिए भारत के कई संगठनों ने इन दोनों देशों का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। पहलगाम आतंकवादी हमले में 26 भारतीयों की जान गई थी। कैट के अनुसार, इस निर्णय में तुर्किये और अजरबैजान की वस्तुओं का राष्ट्रव्यापी बहिष्कार शामिल है। इसमें समूचे भारत के व्यापारी इन देशों से

मीरवाइज फारुक ने भारत व पाक के बीच स्थायी संघर्षविराम की अपील की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

श्रीनगर/भाषा। हुर्रियत कांफ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारुक ने शुक्रवार को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर स्थायी संघर्षविराम की अपील करते हुए कहा कि सैन्य आक्रामकता से केवल विनाश होता है, शांति नहीं। यहां नौहड़ा इलाके में जािमिया मस्जिद में शुक्रवार के जुम्मे की नमाज कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि कश्मीर

एक ‘बिल्कुल ऐसा विस्फोटक बिंदु’ है जो ‘किसी भी समर्थन देकर सकता है।’ उन्होंने कहा, “पिछले कुछ दिनों में हम एक और भयावह अनुभव से गुजरे हैं, जिसमें पिकराल संघर्ष भड़क गया और यह दो परमाणु संपन्न देशों के बीच पूर्ण युद्ध से हमराज कुछ दूर था। यहां तक कि ‘बात थोड़ी भी बिगड़ जाना’ भी जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा के आसपास और पार रहने वाले लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए पर्याप्त था।” मीरवाइज उमर फारुक ने सवाल किया, “हम कब तक इस स्थिति को झेलते रहेंगे तथा भय

‘इंडि’ गठबंधन को लेकर चिदंबरम के बयान पर भाजपा ने कहा कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन के संबंध में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को विपक्षी दल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी के ‘करीबी सहयोगी’ भी जानते हैं कि पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। चिदंबरम ने ‘इंडि’ गठबंधन को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए बृहस्पतिवार को कहा था कि वह आश्चर्य नहीं हैं कि यह विपक्षी गठबंधन अब भी पूरी तरह एकजुट है। चिदंबरम की टिप्पणी पर

प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि जब ‘इंडी’ गठबंधन बना था, तो इसका साझा लक्ष्य सत्ता में आना था, भले ही इसके लिए उसे “भारत विरोधी” बनना पड़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देनी पड़े या सशस्त्र बलों का मनोबल गिराना पड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाताओं ने “घमंड़िया” गठबंधन को नकार

दिया है क्योंकि इसके नेता लोगों की सेवा करने के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ को पूरा करने के वास्ते एक साथ आए थे। भाटिया ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “अब चिदंबरम ने कहा है कि ‘इंडी’ गठबंधन खत्म हो चुका है।” भाजपा के एक अन्य प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार किया है कि भविष्य में विपक्ष एकजुट नहीं रहेगा। भाजपा बहुत मजबूत संगठन है।” उन्होंने कहा, “राहुल गांधी के करीबी सहयोगी भी जानते हैं कि कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है।” चिदंबरम ने सलमान खुशींद और मृत्युंजय सिंह यादव की

किताब “कंटेस्टिंग डेमोक्रेटिक डेफिसिट” के विमोचन के मौके पर कहा था, “भविष्य (इंडिया गठबंधन का) उतना उज्ज्वल नहीं है, जैसा मृत्युंजय सिंह यादव ने कहा। उन्हें लगता है कि गठबंधन अब भी बरकरार है, लेकिन इसे लेकर मैं आश्चर्य नहीं हूं। केवल सलमान (खुशींद) इस पर जवाब दे सकते हैं क्योंकि वह ‘इंडिया’ गठबंधन के लिए बातचीत करने वाली टीम का हिस्सा थे।” पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, “अगर गठबंधन पूरी तरह से कायम है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि यह कमजोर पड़ गया है।” उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि गठबंधन ‘अब भी कायम रह सकता है, अब भी समय है।’

‘जेटो एटम’ आने वाले समय में नीलसन, कंटार का प्रतियोगी होगा : पलीचा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। त्वरित आपूर्ति मंच जेटो के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी आदित पलीचा ने शुक्रवार को कहा कि उनकी कंपनी ‘जेटो एटम’ को एक व्यापक ब्रांड विश्लेषण के तौर पर विकसित कर रही है। पलीचा ने कहा कि ‘जेटो एटम’ आने वाले समय में नीलसन और कंटार जैसी स्थापित बाजार शोध कंपनियों के लिए मजबूत प्रतियोगी साबित होगा। ‘जेटो एटम’ एक व्यापक ब्रांड विश्लेषक टूल है जो जेटो के मंच पर सूचीबद्ध होने वाले ब्रांडों को उनके प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। पलीचा ने कहा, यह न केवल जेटो मंच पर उन ब्रांड को आगे बढ़ने में मदद करेगा, बल्कि इसका विश्लेषण उस ब्रांड के समूचे व्यवसाय के लिए भी उपयोगी होगा। पलीचा ने उम्मीद जताई कि ‘जेटो एटम’ नीलसन और कैंटर के लिए एक अच्छा विकल्प या कम-से-कम एक प्रतिस्पर्धी साबित होगा। इस बारे में टिप्पणी के लिए नीलसन और कंटार को भेजे गए ईमेल के कोई जवाब नहीं मिले। इस टूल को इस्तेमाल करने का शुल्क 90 दिनों के लिए 30,000 रुपये या ब्रांड के पिछले महीने के सकल उत्पाद मूल्य (जीएमपी) का 0.5 प्रतिशत है, जो भी अधिक हो। यह मौजूदा जेटो ब्रांड पोर्टल पर भी आधारित है, जो मुफ्त में बुनियादी प्रदर्शन आंकड़े प्रदान करता है। जेटो एटम अत्यधिक स्थानीय और पिन-कोड के स्तर की बाजार हिस्सेदारी, हर मिनट अद्यतन होने वाले आंकड़े, उन्नत व्यवहार विश्लेषण और ग्राहक खरीद व्यवहार जैसी उन्नत सुविधाएं प्रदान करेगा।

अजित ने कहा-मैं वादे पूरे करने के लिए जाना जाता हूं, विपक्षी राकांपा बोली-नैतिकता के बिना अर्थहीन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। राष्ट्रावादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख व महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने खुद को अपने वादों को पूरा करने के लिए जाना जाने वाला नेता कसूर दिया है, जिस पर प्रतिब्रद्धी राकांपा (शरद चंद्र पवार) ने टुट्टकी लीते हुए कहा कि ‘नैतिकता’ के बिना यह दावा निरर्थक है। महाराष्ट्र के पुणे में पार्टी के कार्यक्रम को संबोधित करते हुये पवार ने कहा, “हर कोई जानता है कि मैं अपने वादे का पक्का हूं। अगर मैं कोई वादा करता हूं, तो उसे पूरा करता हूं। अगर मैं कहता हूं कि मैं किसी को सांसद बनाऊंगा, तो मैं वह भी करूंगा। अगर मैं कहता हूं कि मैं

किसी व्यक्ति की (चुनावी) हार सुनिश्चित करूंगा, तो मैं ऐसा करूंगा। इसके बाद राष्ट्रावादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के प्रवक्ता अमोल मटले ने पवार के दावों पर टुट्टकी लीते हुए कहा, “अजित दादा वाकई अपने वचन के पक्के हैं – आम आदमी के लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों के लिए।” मटले ने कहा, “आपने कहा था कि आप लाड़की बहिन योजना के लाभार्थियों को 2, 100 रुपये देंगे। चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन हमारी प्यारी बहनों को अभी तक 2, 100 रुपये प्रति माह नहीं मिले हैं। जो लोग सत्ता को अपनी पारिवारिक संपत्ति मानते हैं, वे लोकतंत्र के वास्तविक मूल्य को कभी नहीं समझ पाएंगे।” उन्होंने कहा कि देश को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो सच बोलते हों। उन्होंने कहा, “नैतिकता और सिद्धांत के बिना यह शब्द अर्थहीन हैं और अगर इसमें आम आदमी के कल्याण के विचार का अभाव है...।” शरद पवार द्वारा स्थापित राष्ट्रावादी कांग्रेस पार्टी 2023 में विभाजित हो गई जब उनके भतीजे अजित पवार अलग होकर भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार में शामिल हो गए।

रक्षा क्षेत्र की कंपनियों के शेयर में उछाल जारी, पारस डिफेंस में 18.90 प्रतिशत की तेजी

नई दिल्ली/भाषा। झोन विनिर्माताओं, मिसाइल और संबद्ध उपकरणों के विनिर्माताओं समेत रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के शेयर में शुक्रवार को तेजी जारी रही। बीएसएफ पर पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज का शेयर 18.90%, डाटा पेट्रन्स का 9.25%, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स का 7.10%, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स का 5.40%, मिश्र धातु निगम का 4.63%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का 3.87% तथा भारत डायनेमिक्स का 1.95% बढ़ा। झोन विनिर्माता कंपनी ड्रोनार्चा एरिखल इनोवेशन के शेयर में 2% की तेजी आई। घरेलू शेयर बाजारों में बीएसई सेंसेक्स 200.15 अंक की गिरावट के साथ 82,330.59 अंक पर जबकि एनएसई निफ्टी 42.30 अंक फिसलकर 25,019.80 अंक पर बंद हुआ। झोन विनिर्माता कंपनी के बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार और पिछले शुक्रवार को भी रक्षा क्षेत्र की कंपनियों शेयर में तेजी रही थी। पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान एवं उसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू करने के बाद से रक्षा-संबंधित कंपनियों के शेयर में तेजी है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

श्रीनगर/भाषा। सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) के निलंबित रहने के मद्देनजर तुलर झील पर तुलबुल नौवहन बैराज परियोजना का काम फिर से शुरू करने के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आह्वान को लेकर उनके (उमर) और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के बीच शुक्रवार को वाक्युद्ध छिड़ गया। महबूबा ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की टिप्पणी को ‘गैर-जिम्मेदाराना’ और ‘खतरनाक रूप से भड़काऊ’ बताया, जबकि मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि वह इस बात को स्वीकार करने से इनकार कर

रही हैं कि सिंधु जल संधि जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ ‘ऐतिहासिक विश्वासघात’ है, क्योंकि वह ‘ओछे’ प्रचार के लिए और सीमा पार के कुछ लोगों को खुश करने की ‘अंध लालसा’ में डूबी हुई हैं। उमर अब्दुल्ला ने बृहस्पतिवार को ‘एक्स’ पर पोस्ट किया था कि क्या आईडब्ल्यूटी के निलंबन के मद्देनजर तुलर झील पर तुलबुल नौवहन बैराज परियोजना पर काम फिर से शुरू हो सकता है। अब्दुल्ला ने अपने निजी ‘एक्स’ हैंडल पर लिखा,

2020 दिल्ली दंगे: कोर्ट ने 11 लोगों को आगजनी, चोरी के आरोपों से बरी किया

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 के दंगों के एक मामले में आगजनी और चोरी के आरोप में 11 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलरस्व प्रमाचला ने कहा कि मामले में आरोपियों की पहचान करने वाले

दो पुलिस गवाह कृत्रिम प्रत्यक्षदर्शी प्रतीत होते हैं। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि आरोपी व्यक्ति 24 और 25 फरवरी, 2020 की रात को कुछ दुकानों में चोरी, तोड़फोड़ और आगजनी में शामिल थे। अदालत ने 14 मई के आदेश

में कहा कि मामले में मुख्य मुद्दा अपराध करने वाली भीड़ में शामिल आरोपियों की पहचान करना है। अदालत ने कहा कि एक ही पुलिस थाने में तैनात दो पुलिस गवाहों ने 10 महीने के अंतराल के बाद आरोपियों की तस्वीरों की पहचान की।

दो पुलिस गवाह कृत्रिम प्रत्यक्षदर्शी प्रतीत होते हैं

भरेंगे? क्या इस संघर्ष का कभी समाधान होगा?’ ‘कृत्रिम प्रत्यक्षदर्शी’ ने कहा कि ऐसी हर घटना के साथ समस्या और भी मुश्किल होती जा रही है। उन्होंने कहा, “जैसा कि हम जानते हैं और अभी-अभी देखा है, सैन्य अंशेधरता से केवल विनाश ही होता है – शांति कभी नहीं आती। लेकिन कश्मीर के लोग आश्चर्य करते हैं कि क्या भारत और पाकिस्तान शांति चाहते हैं या एक-दूसरे पर हावी होना चाहते हैं।” उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं। मीरवाइज उमर

फारुक ने कहा, “हम समाधान चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि संघर्ष जारी रहे।” उन्होंने कहा कि हमारी दिली तमन्ना है कि दोनों पक्षों के डीजीएमओ द्वारा 18 मई तक घोषित संघर्ष विराम स्थायी हो। उन्होंने सवाल किया कि अगर दोनों देशों के सैन्य अभियान महानिदेशक (डीजीएमओ) बातचीत कर सकते हैं और किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं, तो ‘भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व को ऐसा करने से कौन रोक रहा है?’ उन्होंने कहा, “लेकिन स्पष्ट बात कहना वर्तमान समय में राष्ट्र-विरोधी माना जाता है।

तेलंगाना में बिजली नेटवर्क का आधुनिकीकरण करें अधिकारी : ए रेवंत रेड्डी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

हैदराबाद/भाषा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को अधिकारियों को राज्य में बिजली नेटवर्क का आधुनिकीकरण करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने रेड्डी को बताया कि इस वर्ष बिजली की मांग 17,162 मेगावाट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में नौ प्रतिशत अधिक है। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि बिना किसी रुकावट के बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। अधिकारियों ने रेड्डी को बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उन्नत बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में भी बताया, क्योंकि हैदराबाद डेटा केंद्रों के गढ़ के रूप में उभर रहा है।

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.5 अरब डॉलर बढ़कर 690.61 अरब डॉलर पर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। देश का विदेशी मुद्रा भंडार नौ मई को समाप्त साप्ताह में 4.55 अरब डॉलर बढ़कर 690.62 अरब डॉलर पहुंच गया। मुख्य रूप से स्वर्ण भंडार बढ़ने से कुल विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इसके एक साप्ताह पहले कुल विदेशी मुद्रा भंडार 2.06 अरब डॉलर घटकर 686.06 अरब डॉलर रहा था। सितंबर, 2024 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार 704.89 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, नौ मई को समाप्त

साप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का एक प्रमुख हिस्सा विदेशी मुद्रा आस्तियां 19.6 करोड़ डॉलर बढ़कर 581.37 अरब डॉलर हो गई। डॉलर के संदर्भ में उल्लेखित विदेशी मुद्रा आस्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं की घट-बढ़ का प्रभाव शामिल होता है। सभीभाषीन साप्ताह में स्वर्ण भंडार का मूल्य 4.52 अरब डॉलर बढ़कर 86.34 अरब डॉलर हो गया। विशेष आह्वान अधिकार (एसडीआर) 2.6 करोड़ डॉलर घटकर 18.53 अरब डॉलर रहा। केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के अनुसार, आलोच्य साप्ताह में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के पास भारत का आरक्षित भंडार 13.4 करोड़ डॉलर घटकर 4.37 अरब डॉलर रहा।

पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजेगी सरकार

नई दिल्ली/भाषा। सरकार पहलगाम में आतंकवादी हमले के जवाब में चलाए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद आक्रामक राजनयिक अभियान के तहत वैश्विक मंच पर भारत के पक्ष को मजबूती से रखने और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब करने के लिए अलग-अलग से विभिन्न देशों में कई बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजेगी। सत्ताकण्ड भाजपा और मुख्य विपक्षी कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों से सरकार ने इसके लिए आह्वान किया है और कुछ दलों ने राजनयिक प्रयास के लिए सदस्यों को भेजने की मंजूरी भी दे दी है। सूत्रों ने कहा कि कुछ पूर्व केंद्रीय मंत्री इन प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश जाने वाले इन प्रतिनिधिमंडलों या उनके सदस्यों का सट्टा को लेकर फिलहाल कोई स्पष्टता नहीं है, हालांकि कुछ नेताओं ने कहा कि 30 से अधिक सांसद हो सकते हैं। प्रतिनिधिमंडल 10 दिनों की अवधि के लिए विभिन्न देशों का दौरा करेंगे। सांसद सरकार द्वारा निर्धारित देशों का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय इस राजनयिक मिशन के लिए रवाना होने से पहले सांसदों को पूरी जानकारी देगा। सूत्रों ने बताया कि जिन पार्टियों के सांसद प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे उनमें भाजपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, राष्ट्रावादी कांग्रेस पार्टी (एसपी), जनता दल (यूनाइटेड), बीजू जनता दल, माकपा और कुछ अन्य शामिल हैं।

हवाई अड्डों से समझौते खत्म करने को चुनौती देने के कानूनी तरीके अपनाएं: सेलेबी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। तुर्किये की कंपनी सेलेबी हावा सर्विसी एस ने शुक्रवार को कहा कि भारत में उसकी सुरक्षा मंजूरी रद्द किए जाने के बाद विभिन्न लाइसेंस और रियायती करारों को एकतरफा ढंग से खत्म करने को चुनौती देने के लिए सभी उपलब्ध प्रशासनिक और कानूनी उपायों का इस्तेमाल किया जाएगा। नगर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएस) ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय सुरक्षा हितों का हवाला देते हुए हवाई अड्डे पर जमीनी रखरखाव एवं मालवहन सेवाएं देने वाली कंपनी सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी थी। हाल ही में तुर्किये द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करने और पड़ोसी देश में

आतंकी शिविरों पर भारत के हवाई हमलों की निंदा करने के कुछ दिनों बाद सेलेबी के खिलाफ यह कदम उठाया गया है। देश भर में तुर्किये को लेकर लोगों में असंतोष और नाराजगी देखी जा रही है। सेलेबी दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद सहित नौ हवाई अड्डों पर अपनी सेवाएं दे रही थी। करीब 15 वर्षों से भारतीय से विमानन क्षेत्र में सक्रिय सेलेबी 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार दे रही है। इस क्रम में बीसीएस के फैसले के बाद सेलेबी हावा सर्विसी एस की विभिन्न संस्थाओं के संचालन को निलंबित कर दिया गया है। इनमें सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्रा. लि. (सीएसएसआई), सेलेबी जीएच इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सीजीएचआई) और अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के बीच लाइसेंस समझौता समाप्त कर दिया गया है जो 2032 तक वैध था।

दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सेलेबी जीएस चेन्नई प्राइवेट लिमिटेड (सीजीएससी) शामिल हैं। तुर्किये के शेयर बाजार को दी गई एक सूचना में सेलेबी ने कहा कि इसकी अनुबंधी कंपनियों और संबंधित भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरणों के बीच निष्पादित चार रियायत एवं लाइसेंस समझौतों को एकतरफा ढंग से खत्म कर दिया गया है। सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. (डायल) के बीच निष्पादित रियायत समझौता वर्ष 2034 तक वैध था। सेलेबी जीएच इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सीजीएचआई) और अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के बीच लाइसेंस समझौता समाप्त कर दिया गया है जो 2032 तक वैध था।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakhshinbharat.com

बेंगलूर। अंतरराष्ट्रीय कृष्णभावनामृत संघ (इस्कॉन) बेंगलूर ने शुक्रवार को कहा कि यहां स्थित इस्कॉन मंदिर के संबंध में उच्चतम न्यायालय के फैसले ने "स्वयंभू गुरुओं" के खिलाफ लंबी लड़ाई और श्रील प्रभुपाद को उनकी महासमाधि के बाद इस संस्था के आचार्य के रूप में स्थापित करने के श्रद्धालुओं के लंबे संघर्ष को समाप्त कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि बेंगलूर में हरे कृष्ण मंदिर, इस शहर में स्थित इस्कॉन सोसाइटी का है। न्यायालय ने इस्कॉन बेंगलूर की याचिका स्वीकार कर ली, जिसमें कानूतिक उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें इस्कॉन मुंबई के पक्ष में उद्घाटन के हरे कृष्ण मंदिर और शैक्षणिक परिसर पर नियंत्रण का आदेश दिया गया था।

इस्कॉन बेंगलूर के अध्यक्ष मधु पंडित दास ने एक बयान में कहा, यह इस्कॉन की आंतरिक लड़ाई उन स्वयंभू गुरुओं के खिलाफ थी, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद के उत्तराधिकारी होने का दावा करते थे, जबकि उन्हें श्रील प्रभुपाद के महासमाधि लेने से पहले इसकी अनुमति नहीं थी। उन्होंने कहा, बल्कि, उन्होंने एक ऋत्विक् प्रणाली स्थापित की, जिसके तहत इस्कॉन में सभी श्रद्धालु हर समय श्रील प्रभुपाद के प्रत्यक्ष शिष्य होंगे।

इस्कॉन के संस्थापक-आचार्य श्रील प्रभुपाद ने महासमाधि से कुछ समय पहले 1977 में दीक्षा की एक प्रणाली शुरू की। ऋत्विक् प्रणाली के रूप में जानी जाने वाली इस प्रणाली में दीक्षा उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों के माध्यम से दी जाती है। इस व्यवस्था के अनुसार, भविष्य के सभी श्रद्धालु श्रील प्रभुपाद के प्रत्यक्ष शिष्य बन जाते हैं, जो इस्कॉन के आचार्य बने रहते हैं। उन्होंने

आरोप लगाया कि वर्ष 2000 में इस्कॉन मुंबई के लोगों ने इस्कॉन बेंगलूर के श्रद्धालुओं को निष्कासित करने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने इस्कॉन के स्वयंभू गुरुओं की गुरुता को स्वीकार करने से इस्कार कर दिया। उनका दावा था कि इस्कॉन मुंबई सोसायटी, इस्कॉन बेंगलूर सोसायटी की संपत्तियों का स्वामित्व रखती है। दास ने कहा, "आज, 25 साल पुरानी अदालती लड़ाई उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले से समाप्त कर दी है, जिसमें कहा गया है कि बीडीए (बेंगलूर विकास प्राधिकरण) ने इस्कॉन बेंगलूर सोसायटी को मंदिर की जमीन आवंटित की थी - जो बेंगलूर में पंजीकृत एक स्वतंत्र इस्कॉन सोसायटी है और संपत्ति और मंदिर निर्माण के लिए धन बेंगलूर में जुटाया गया था।"

उन्होंने कहा, "इस्कॉन मुंबई को इस्कॉन बेंगलूर के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने से रोक दिया गया है। वे अब इस्कॉन से उन हजारों श्रद्धालुओं को निष्कासित नहीं कर सकते जो केवल श्रील प्रभुपाद को ही इस्कॉन के एकमात्र आचार्य मानना चाहते हैं।" इस्कॉन बेंगलूर ने 23 मई 2011 के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए 2 जून 2011 को शीर्ष अदालत का रुख किया था।

इस्कॉन बेंगलूर ने अपने पदाधिकारी कोडेराराम दास के मार्फत याचिका में उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें बेंगलूर की एक स्थानीय अदालत के 2009 के आदेश को पलट दिया गया था। निचली अदालत ने पहले इस्कॉन बेंगलूर के पक्ष में फैसला सुनाया था, उसके कानूनी अधिकार को मान्यता दी थी और इस्कॉन मुंबई के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा जारी की थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस फैसले को पलट दिया और इस्कॉन मुंबई के जवाबी दायों को बरकरार रखा, जिससे प्रभावी रूप से उसे मंदिर का नियंत्रण मिल गया था।

पलकड़/भाषा। केल की एक अदालत ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को 2022 में पलकड़ स्थित 15 वर्षीय लड़की के आवास पर उससे बलात्कार कराया की कहर और उसे "गर्भपाती करण" के जुर्म में दोहो आजीवन कारावा की सजा सुनाई। पीडिता आरोपी की रिश्तेदार नहीं। विश्व लोक अभियोजक (एसपीपी) निशा विजयकुमार ने कहा कि पटवारी निदेश विशेष अदालत के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संजू टी. ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पावर्स) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आरपीसी) के विभिन्न प्रावधानों के तहत व्यक्ति को 43 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। एसपीपी ने बताया कि अदालत ने निर्देश दिया है कि 49 वर्षीय व्यक्ति को को पहले 43 साल सभ्य कारावास की सजा काटनी होगी और फिर पावर्स अधिनियम के अला-आवस प्रावधानों के तहत उसकी आजीवन कारावास की सजा शुरू होगी। अदालत ने आरोपी पर चार लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और जुर्माने की राशि को पीडिता को देने का निर्देश दिया। अभियोजक ने बताया कि अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीडिता को अतिरिक्त मुआजजा देने का भी निर्देश दिया। अभियोजक ने कहा के अनुसार, आरोपी ने पीडिता के घर पर उससे बलात्कार किया, जिसके कारण "वह गर्भपाती हो गई"। घटना के एक घर पर कोई मौजूद नहीं था।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलुरु। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने शुक्रवार को कहा कि 'पाकिस्तान की घटना के बाद' केंद्र सरकार के विशेष निर्देशों के तहत तटीय सुरक्षा अधिकारियों ने एक इराकी मालवाहक जहाज के चालक दल को कर्नाटक के कारवार बंदरगाह पर उतरने की अनुमति नहीं दी गई। बंदरगाह के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इराकी मालवाहक जहाज के चालक दल को कारवार बंदरगाह पर उतरने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि उनमें पाकिस्तानी और सीरियाई नागरिक शामिल थे। उन्होंने बुधवार को कहा कि उनको वापस भेज दिया गया।

इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए परमेश्वर ने यहां संवाददाताओं से कहा, पाकिस्तान की इस घटना के बाद भारत सरकार ने सभी सशस्त्र बलों और राज्य विभागों को विशेष निर्देश दिए हैं। इसलिए एक राज्य के तौर पर हमारे पास तटीय सर्वेक्षण बल है... उन्होंने (कारवार बंदरगाह पर इराकी मालवाहक पोते के चालक दल को उतरने से) दोष दिया। परमेश्वर ने कहा कि स्वाभाविक रूप से भारत के जल क्षेत्र में प्रवेश देने से पहले प्रत्येक जहाज की जांच की जाएगी, इसलिए उन्होंने अच्छा

काम किया है। वरिष्ठ बंदरगाह अधिकारियों के अनुसार, इराक के एक जुबैर से रवाना हुआ यह पोत बिल्हून लेकर कारवार में खड़ा था। इसके चालक दल में 15 भारतीय, एक पाकिस्तानी और दो सीरियाई नागरिक शामिल थे। उन्होंने कहा कि मानक निरीक्षण प्रोटोकॉल का कड़ी सतर्कता के बाद, पोत पर पाकिस्तानी और सीरियाई नागरिकों की मौजूदगी के कारण बंदरगाह अधिकारियों और तटीय सुरक्षा पुलिस ने सुरक्षा संबंधी कार्रवाई की।

संचार को प्रतिबंधित करने के लिए पोते के कप्तान के माध्यम से उनके मोबाइल फोन जप्त कर लिए गए और माल उतारने तक उन्हें दो दिनों तक पोत पर ही रोक रखा गया। इसके बाद पोत अपने अगले गंतव्य के लिए रवाना हो गया।

बेंगलूर। कर्नाटक के विकिरेखा प्रकाश और कौशल विकास मंत्रि शरण प्रसाद पाटिल ने शुक्रवार को घोषणा की कि कौशल विकास विभाग में अब सभी सामान्य तबादले परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से किए जाएंगे। विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान पाटिल ने कौशल विकास सचिव एकरूप कोर को नयी प्रणाली के लिए व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया, जिसमें रोजगार और प्रशिक्षण विभाग (डीईटी) पर विशेष ध्यान दिया गया। मंत्री ने एक बयान में कहा, प्रभाव और सफाई के माध्यम से तबादलों की मांग की प्रथा को समाप्त करने के लिए अब सभी तैनाती परामर्श के माध्यम से की जानी चाहिए। इससे कर्मचारियों को पसंदीदा स्थानों पर तैनाती प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। पाटिल ने याद दिलाया कि सरकार सबसे पहले ही सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के सामान्य तबादलों के लिए 16 जून की समय सीमा तय कर दी है। प्रशासनिक अक्षमता पर कड़ा रुख अपनाते हुए पाटिल ने सरकारी कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने में "नाकामी" के लिए विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की आलोचना की। उन्होंने सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी करने और संबंधित अधिकारियों को बिना देरी किए स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोप्पल। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने शुक्रवार को कहा कि राज्य का कांग्रेस सरकार को दो साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 20 मई को विजयनगर जिले के होस्पेट में आयोजित कार्यक्रम में करीब तीन लाख लोगों को शामिल होने की उम्मीद है। उन्होंने प्रकाशों से बातचीत में कहा कि कार्यक्रम के दौरान ऐसे पात्र भागार्थियों को एक लाख भूमि-पट्टे वितरित किए जाएंगे जिनकी अवैध 'स्तित्तियों' को राजस्व गांव घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही अन्य विभागों द्वारा भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'हम पिछले दो वर्षों की अपनी उपलब्धियों को लोगों के सामने पेश करने का प्रयास करेंगे।' मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या और उपमुख्यमंत्री टी. के. शिवकुमार, दोनों ने पहले संकेत दिया था कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खेरे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।

वृद्ध बेंगलूर शासन अधिनियम की विपक्षी भाजपा द्वारा की जा रही आलोचना पर सिद्धरामय्या ने कहा कि सुरेश कुमार के शहरी विकास मंत्री रहने के दौरान भाजपा ने ही बेंगलूर नगर निगम को विभाजित करने का फैसला किया था। वृद्ध बेंगलूर शासन अधिनियम 15 की को लागू हुआ था और यह अधिनियम बेंगलूर शहर के प्रबंधन के लिए अधिकतम सात नगर निगमों के गठन की अनुमति देता है। उन्होंने कहा, 'जब मैं पहली बार

एकदमगी बना, तो प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए, हमने शहर में तीन या अधिक नगर समिति बनाने के लिए एक संधि बनाई। इसका नाम लौटने के बाद, हमने (कांग्रेस सरकार ने) इस प्रक्रिया को जारी रखा है।” अधिनियम शहर के प्रबंधन के लिए अधिकतम सात नगर समितियों के गठन की अनुमति देता है और ऐसे संकेत हैं कि नगर सरकार विचार-विमर्श के बाद तीन नगर समिति बनाने का फैसला कर सकती है। एक देवाल के जवाब में, सिरहामय्या ने जो संकर कहा कि जब भी गंगावती

उपचुनाव होगा, कांग्रेस जीतेगी।
यह सीट कनकट विधानसभा के सदस्य के रूप में जी जगानंद रेड्डी को अयोग्य घोषित किये के बाद रिक्त हुई हैं।
हैदराबाद की एक विशेष सीबीआई आदालत ने उन्हें ओबुलपुस्रम माईनिंग कंपनी (ओएमसी) के अवैध लौह अयस्क खनन मामले में दोषी करार दिया था।
सिद्दरामय्या ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार की पांच गारंटी योजनाएँ (गृह लक्ष्मी, शक्ति, गृह ज्योति, अन्न भाग्य और युवा निधि) में से किसी के लिए भी धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा, "पिछले साल मैंने इसके लिए बजट में 52,009 करोड़ रुपये आवंटित किए थे और इस साल मैंने 50,018 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। धन की कोई कमी नहीं है।"





सुविचार

जो व्यक्ति अपना लक्ष्य
तय नहीं कर सकता,
वह जीत भी नहीं सकता।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

शब्दों की मर्यादा न भूलें

भारत के वीर सैनिकों ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत बहादुरी और बलिदान की जो मिसाल पेश की, उसके लिए देशवासी उनकी जय-जयकार कर रहे हैं। हमारे सैनिक इन तारीफों के हकदार हैं, लेकिन कुछ नेताओं ने जो बड़बोलापन दिखाया, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह कोई सियासी नृरा-कुशती नहीं है कि एक नेता दूसरे नेता को ललकारे, वह उसे कुछ खास शब्दों से नवाज़े और उसके समर्थक इस जुबानी जंग का लुत्फ उठाते हुए बालियां खाएं। हमारी सेनाओं का देशवासी बहुत सम्मान करते हैं। एक सैनिक जब देश के दुश्मनों से भिड़ता है तो वह अपने प्राण देने से भी नहीं हिचकता। नेतागण उनके बारे में कोई बयान दें तो शब्दों की मर्यादा का खास ध्यान रखें। भारत का सैनिक किसी जाति और मजहब के लिए नहीं लड़ता। वह पूरे देश के लिए लड़ता है। उसके लिए समस्त देशवासी ही अपने होते हैं। जो लोग सैनिकों के बारे में भेदभावपूर्ण टिप्पणियां करते हैं, वे राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को हतोत्साहित करना चाहिए। जो नेता अपने मुद्दीभर समर्थकों के बीच इस किसम की बयानबाजी कर तालियों से खुश हो जाते हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि देशभर में उनकी भारी किरकिरी हो रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी ... हम सभी भारत मां की संतानें हैं। देश को सुरक्षित और एकजुट रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारी सेनाओं में हर धर्म और जाति के लोग सेवाएं दे रहे हैं। उन सबमें महान बलिदानी पैदा हुए हैं। हमें तो इस विविधता को अपनी ताकत समझना चाहिए। भारत वह देश है जिसकी विविधता ऐसे सैनिक तैयार करने में सक्षम है, जो हर किसम के वातावरण में तैनात हो सकते हैं, लड़ सकते हैं। हमारी सांस्कृतिक जड़ें बहुत गहरी हैं।

इस समय रूस-यूक्रेन युद्ध चल रहा है और दोनों ही देशों की सेनाएं सैनिकों की कमी से जूझ रही हैं। उनकी सरकारों द्वारा नौजवानों को सेना में जबरन भर्ती किए जाने की खबरें भी आई हैं। कई नौजवान इससे बचने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। कई तो विदेशों में शरण ले चुके हैं। भारत में स्थिति बिल्कुल अलग है। यहां ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का आगाज होते ही नौजवान केंद्र सरकार से कह रहे हैं कि हमें सेना में भर्ती कीजिए। सरहद्दी इलाकों में ग्रामीण कह रहे हैं कि अगर युद्ध छिड़ा तो हम कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि यहीं रहकर सैनिकों का सहयोग करेंगे। जिस देश में सेना के साथ जनभावनाएं इतनी मजबूती से जुड़ी हों, वहां कुछ ओछी टीका-टिप्पणी करने वालों की चालें कभी कामयाब नहीं हो सकती हैं। जब भारतीय सैनिक बर्फीली वादी, जंगल, रेगिस्तान, समुद्र और आकाश में दुश्मन से लड़ता है तो वह सिर्फ भारतीय होता है। वह या तो तिरंगा फहराकर आता है या तिरंगे में लिपटकर आता है। बहुत दूर न जाएं, कारगिल युद्ध की कहानियां ही पढ़ लें। मेजर सोनम वांगचुक, कैप्टन विजयंत थापर, राइफलमैन संजय कुमार, कैप्टन अनुज नय्यर, कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर राजेश सिंह, कैप्टन हनीफ़ुद्दीन जैसे योद्धा किसके लिए लड़े थे? ये भारत मां के लिए लड़े थे, उसकी करोड़ों संतानों के लिए लड़े थे। ये देश की अखंडता के लिए लड़े थे। दुश्मन की गोलाबारी और सख्त मौसमी हालात के बीच भारतीय सैनिक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे थे, तो इसके पीछे उनका अटूट देशप्रेम था। जिसके दिल में देशप्रेम की ज्वाला होती है, उसे मौत का खौफ नहीं होता। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ भी ऐसी एक ज्वाला है। संकुचित सोच रखने वाले कुछ नेता अपनी भेदभावपूर्ण टिप्पणियों के जरिए वोटबैंक में बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं तो उन्हें निराशा ही हाथ लगेगी। भारतवासी अपनी सेनाओं के साथ एकजुट हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सैनिकों की नहीं, हम सबकी है।

ट्वीटर टॉक



आज मंगलुरु प्रवास के दौरान श्री मंजुनाथ मंदिर, धर्मस्थल में भगवान श्री मंजुनाथ जी के दर्शन कर पूजा अर्चना की एवं देशवासियों के कल्याण और सुख-समृद्धि की प्रार्थना की। यह पावन धाम हमारी सनातन संस्कृति, आस्था और परंपराओं की गौरवशाली पहचान है।

—अर्जुनम मेघवाल

शौर्य, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक, वीर शिरोमणि वीर शिरोमणि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती पर सादर नमन। मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने जिस वीरता और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया, वह भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है।

—ओम बिरला



वीरता, शौर्य और उदारता की अद्वितीय प्रतिमूर्ति, ‘राजस्थान गौरव’ वीर शिरोमणि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। आपकी गौरव गाथा युगों-युगों तक मातृभूमि के कण-कण को गौरवान्वित करती रहेगी।

—भजनलाल शर्मा

प्रेरक प्रसंग

शुम-अशुम निहितार्थ

अमेरिका के प्रसिद्ध हास्य लेखक मार्क ट्वेन एक पत्रिका का संपादन कर रहे थे। एक दिन उन्हें एक पाठक का शिकायत भरा पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था कि जब वह अखबार पढ़ रहा था, तब उसमें से एक मकड़ी निकल आई। पाठक ने सवाल उठाया कि अखबार में से मकड़ी निकलना शुभ माना जाए या अशुभ? मार्क ट्वेन ने बड़े रोचक और व्यंग्यपूर्ण ढंग से उत्तर दिया, ‘शायद आपको यह नहीं पता कि हमारी पत्रिका को मकड़ियां भी पढ़ती हैं। उनका भी एक उद्देश्य होता है। वे यह देखती हैं कि किन दुकानदारों ने इस अंक में विज्ञापन नहीं दिया है। जिन दुकानों के विज्ञापन नहीं होते, वहां ग्राहक नहीं आते और बिक्री ठप रहती है। ऐसे में मकड़ियां निश्चित होकर उन्हीं दुकानों में घुस जाती हैं। दरवाजा पर पर जाके बुनती हैं और भीतर रखी वस्तुओं का आनंद लेती हैं। इसलिए जिन दुकानदारों ने विज्ञापन दिया है, उनके लिए तो मकड़ी का निकलना शुभ है यह संकेत है कि उन्होंने सही निवेश किया। लेकिन जिनका विज्ञापन नहीं छपा, उनके लिए यह अशुभ संकेत है कि उनकी दुकान में अब सिर्फ मकड़ियां ही आएंगी!’

महत्त्वपूर्ण

Printed & Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company,6/4 , 1st floor, Cantonment station road, Bengaluru-51and printed at Dinasadur Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekanth Parashar.** (Responsible for selection of news under PRB Act). Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.RNI No. 58061/93. Regn.No.: RNP/KA/BGS/2050/2015-2017 posted at Bengaluru PSO Mysore Road Bengaluru-560 026

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वरीकृत, टेंडर एवं सजायदी इत्यादि) पर कोई भी कायवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी यह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उद्योगों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रण एवं प्रकाशक या मालिकाना को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता। — दक्षिण भारत राष्ट्रमत

सामयिक

अरुणाचली चाल है पाक के हक में चीन की बौखलाहट

ललित गर्ग

मोबाइल : 9811051133

पहलगां आतंकी हमले के बाद भारत के सफल ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद चीन बौखला गया है। पाकिस्तान की करारी हार एवं उसे दिये गये सबक को चीन पचा नहीं पा रहा है। चीन-पाक की सदाबहार दोस्ती के उदाहरण बार-बार सामने आते रहे हैं, हाल ही में सैन्य टकराव के दौरान चीन ने प्रत्यक्ष व परोक्ष तौर पर पाकिस्तान का समर्थन ही नहीं किया, बल्कि सैन्य व आर्थिक मदद भी की। ऐसे ही संवेदनशील समय पर चीन ने भारतीय जमीन पर दावेदारी जताने एवं अरुणाचल के 27 स्थानों को चीनी नाम देने की कुचैष्टा की है। उसकी यह नापाक कोशिश भी पाक के साथ खड़े होने का ही प्रयास है। यह ध्यान रहे कि वह अरुणाचल एवं उसके अनेक क्षेत्रों, इनमें आवासीय क्षेत्रों के साथ पहाड़ और नदियां भी हैं, इनको पहले ही चीनी नाम दे चुका है। भारत सरकार ने अरुणाचल के भीतरी स्थानों को नए नाम देने के चीन के निराधार और बेतुके प्रयासों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए इसकी निन्दा की है। चीन अपनी दोगली नीति, षडयंत्रकारी हरकतों एवं विस्तारवादी मंशा से कभी बाज नहीं आता। वह हमेशा कोई ऐसी कुचैष्टा करता ही रहता है जिससे भारत चीन बॉर्डर पर अक्सर तनाव रहता है। हालांकि भारत ने दो दूक जवाब देते हुए साफ कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और यह चीनी दुष्प्रचार के सिपाय कुछ नहीं है। चीन की इस हरकत ने यह साफ कर दिया है कि उससे संबंध सुधारने की भारत की तरफ से कितनी ही पहल हो जाए, वह सुधारने वाला नहीं है।

निश्चित ही चीन की ये दकियानूसी हरकतें पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं, यह उसके दुरसाहस एवं उच्छृंखलता का द्योतक है। नाम बदलने से इस स्पष्ट और निर्विवाद वास्तविकता को नहीं बदला जा सकता कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। इस तरह की करतूतों, बचकानी एवं बेतुकी हरकतों से भारत को उकसाना चाहता है। इसी नीति के तहत वह भारत के पड़ोसी देशों में अपनी पैठ बना कर पुलों, सड़कों, व्यावसायिक केंद्रों आदि का निर्माण कर भारत की सीमा पर तनाव पैदा करने की भी



कोशिश करता रहा है। शायद उसने यह गुगलता पाल लिया है कि ताजा घटनाक्रम से भारत दबाव में आ जाएगा लेकिन भारत अब ऐसे किसी दबाव में न तो आयेगा, बल्कि इनका सक्षम एवं तीक्ष्ण तरीके से जवाब देने में भारत सक्षम है। चीन का अधिक बौखलाहट एवं खीज का बड़ा कारण भारत ने उसके एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन, मिसाइल आदि की इस कदर पोल खोल कर रख दी कि अब उसके लिए दुनिया के निर्धन देशों को अपने दायम दर्ज एवं घटिटा किस्म के चीनी हथियार बेचना कठिन होगा। पाकिस्तान ने जिस चीनी मिसाइल का इस्तेमाल किया था, उसे भारत ने नाकाम कर दिया।

चीन यह तो चाहता है कि भारत उसके हितों को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरते, लेकिन खुद उसकी ओर से भारत के प्रति अपेक्षित संवेदनशीलता को लगातार नजरअंदाज करता है। चीन भरोसे लायक देश नहीं है, चीन के प्रति कठोर रायें जरूरी हैं। निरसंदेह नाम बदलने जैसी घटनाएं हमें सतर्क करती हैं कि चीन के साथ मैत्री संबंधों के निर्धारण के दौरान हमें सतर्क, सावधान व सचेत रहना चाहिए। अन्यथा चीन पीठ पर वार करने से नहीं चूकने वाला है। भारत को चीन के साथ अपनी तिब्बत नीति पर भी नए सिरे से विचार करना होगा। पिछले तीसरे साल में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के अनेक स्थानों के नाम बदले हैं। चीन अरुणाचल को जांगनान के नाम से दर्शाता है। वहीं इसे तिब्बत के दक्षिणी हिस्से के रूप में होने का दावा करता है। चीन किये गये वायदों एवं समझौतों से पीछे हटता रहा है, चीनी राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच 1993, 1996, 2005 और 2013 में परस्पर भरोसा पैदा करने वाले समझौतों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने अपनी सेना को भारतीय दावे वाले

इलाकों में अतिक्रमण करने का आदेश दिया। इसी का अंजाम रही जून 2020 में गलवान घाटी जैसी घटना। जिसमें उसके सैनिक गलवान घाटी में घुस आए थे, जिन्हें रोकने में खूनी संघर्ष हुआ। तबसे दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। भारत के हिस्से की जमीन पर कब्जा करने के इरादे से वह चोरी-छिपे और चालबाजी से घुसपैठ करने की कोशिशें करता रहता है। चीन की विस्तारवादी नीति भारत सहित सम्पूर्ण एशिया के लिये ही नहीं, पूरे विश्व के लिए बड़ा खतरा है।

चीन भारत की बढ़ती ताकत एवं रूतबे से परेशान है। भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत चीन को चुभती रही है, इसलिए वह चोरी, चालाकी और चालबाजी से भारत को कमजोर करने की चालें चलता रहता है। दरअसल, सीमाओं को लेकर नित नए विवादरूपद तथ्य लाना चीन की फितरत में शामिल है। अरुणाचल प्रदेश ही नहीं, अक्साई चिन, ताइवान और विवादित दक्षिण चीन सागर पर भी चीन अपना दावा जताता रहा है। शांति और चालबाज चीन अरुणाचल के किसी दस्तावेज पर भारत का नाम स्वीकार नहीं करता। कुछ मौकों पर तो वह अरुणाचल को अपने नक्शे में शामिल कर दुनिया के सामने साबित करने की कोशिश कर चुका है कि वह उसका इलाका है। मगर भारत की तरफ से मिले सख्त प्रतिरोध की वजह, सामरिक शक्ति और रणनीतिक सूझ-बूझ से उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी है।

भारत को अनेक मोर्चों पर चीन को आड़े हाथ लेना होगा, सबसे जरूरी है चीन सामान का बहिष्कार, इस पर सरकार के साथ हमारे उद्योग जगत एवं आम जनता को भी गंभीरता से सोचना होगा। ऐसा करने ही चीन की कमर को तोड़ना जा सकता है, आज दुनिया के अनेक देश चीनी

हेल्थ

बीपी ने बढ़ाई दिल की धड़कन

बाल मुकुन्द ओझा

मोबाइल : 9414441218

विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हर वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। दरअसल आजकल की सभी बीमारियां खराब जीवनशैली से जुड़ी होती हैं, ऐसे में ब्लड प्रेशर की समस्या को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए हमें लाइफ स्टाइल में सुधार करने की जरूरत होती है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2025 की थीम, अपने रक्तचाप को सही तरीके से मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जिएं रखी गई है। इसका मतलब है कि नियमित और सटीक रक्तचाप माप के महत्व पर जोर देना आवश्यक है। डॉक्टर के मुताबिक, हाईपरटेंशन के सही प्रबंधन की आधारशिला ही सटीक रक्तचाप माप है। सही मेजरमेंट बीपी को जल्दी पहचानने, प्रभावी ढंग से मैनेज करने और जोखिमों से बचने में मदद करता है। चिकित्सकों ने सही मेजरमेंट के लिए बताया है, बीपी चेक करने से पहले मरीज को कम से कम 5 मिनट तक आराम करने दें। बीपी चेक करवाते समय बातचीत न करें और मरीज की पीठ तथा हाथ ठीक से टिके हों। दो या अधिक बार बीपी चेक करें और औसत माप निकालें। घर पर बीपी मापना भी फायदेमंद होता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों में हाई ब्लड प्रेशर के प्रति जागरूक करना है। इस बीमारी ने अब घर घर दस्तक दे दी है जिस कारण इसे साइलेंट किलर भी कहा जाने लगा है। इसका कारण यह



हैं कि कई बार बीपी के लक्षण शुरूआती चरणों में दिखाई नहीं देते हैं और यह धीरे-धीरे हार्ट, ब्रेन, किडनी एवं आंखों जैसे महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है।

भारत की बात करें तो हमारा देश आजकल बीमारियों के देश के रूप में अपनी पहचान बनाता जा रहा है। इनमें एक बीमारी बीपी या उच्च रक्तचाप की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में करीब 20 करोड़ लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। इनमें से 37 प्रतिशत मरीजों को अपनी बीमारी के बारे में पता है और 30 प्रतिशत हाईब्लड प्रेशर के लिए इलाज ले रहे हैं। भारत में केवल 15 प्रतिशत मरीजों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है। यह

बीमारी साइलेंट किलर के रूप में घर घर में देखने को मिल रही है। आज के आधुनिक परिवेश में ब्लड प्रेशर के मरीजों की तादाद दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। दौड़-भाग भरी जिंदगी, फॉस्ट फूड और अनियमित दिनचर्या की वजह से आजकल बच्चे से बुजुर्ग तक हर उम्र के लोगों में बीपी की समस्या देखने को मिल रही है। और वैसे तो ब्लड प्रेशर की बीमारी मामूली सी लगती है लेकिन अगर इसपर काबू न पाया गया तो यह समस्या दिल की बीमारी, स्ट्रोक और किडनी की बीमारी का कारण भी बन सकती है। ब्लड प्रेशर कम हो या ज्यादा दोनों ही खतरनाक होते हैं। इसलिए डॉक्टर द्वारा अक्सर यह सलाह दी जाती है की आप नियमित रूप से ब्लड प्रेशर की जांच करवाते रहें। देश में ज्यादा नमक ने दिल का और हाई ब्लडप्रेशर मरीज बना दिया है। 25 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में भारत में नमक का औसत सेवन 10 ग्राम प्रतिदिन है। जबकि थकज के मुताबिक एक व्यक्ति को एक दिन में 5 ग्राम या उससे भी कम नमक खाना चाहिए। लेकिन भारतीय रोजाना डबल डोज में नमक खा रहे हैं, जिसमें पुरुष औसतन 11 ग्राम और महिलाएं 9 ग्राम नमक खा रही हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा रहता है वो हाईब्लड प्रेशर के मरीज माने जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के मुताबिक अगर 50 प्रतिशत लोगों को कंट्रोल ब्लड प्रेशर वाले दायरे में लाया जा सका तो 2023 से 2050 के बीच होने वाली 76 मिलियन यानी साढ़े सात करोड़ लोगों की असमय मौतों को टाला जा सकेगा।

नजरिया

धार्मिक उग्रवाद के विरोध में धर्मनिरपेक्षता एक बड़ी शक्ति

संजीव ठाकुर

मोबाइल : 9009 415 415

धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्र को सशक्त करने हेतु एक महत्वपूर्ण संवेदनशील एवं शाश्वत सिद्धांत है। धर्मनिरपेक्षता भारतीय राजनीति का मूल आधार तत्व है। जिसमें राजनीतिक दलों को भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका अंतर्निहित है। धर्मनिरपेक्षता धार्मिक उग्रवाद का बड़ा विरोधी भाव है। इसमें धर्म के प्रति विवेक का भाव नहीं होता है, बल्कि सभी धर्मों का समान आदर किया जाता है। इस आधुनिक काल में धर्मनिरपेक्षता सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत में प्रस्तुत सर्वाधिक जटिल शब्दों में एक है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ पाश्चात्य तथा भारतीय संदर्भ में अलग-अलग है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य समाज में विभिन्न धार्मिक मतों का अस्तित्व मूल्यों को बनाए रखने सभी मतों का विकास और समृद्धि करने की स्वतंत्रता का तथा साथ ही साथ सभी धर्मों के प्रति एक समान आदर तथा सहिष्णुता विकसित करना भी है। पश्चिमी संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जहां धर्म और राज्यों का एक दूसरे के



मामले में हस्तक्षेप न करना तथा व्यक्तियों और उनके अधिकारों को केंद्रीय महत्व दिया जाना शामिल है। यद्यपि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में पश्चिमी भाव तो शामिल हैं साथ-साथ कुछ अन्य भाव भी शामिल किए गए हैं। धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति समाज या राष्ट्र अभाव होता है, जो किसी विशेष धर्म या अन्य धर्मों की तुलना में पक्षपात नहीं करता है।

भारतीय संदर्भ धर्मनिरपेक्षता की आजादी के बाद बड़ी स्वरूप एवं स्वरथ सार्वभौमिक परंपरा रही है। इसमें किसी व्यक्ति से धर्म और संसदाय के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। प्रत्येक नागरिक को इसके अंतर्गत स्वतंत्रता प्राप्त

होती है कि वह अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपनाना एवं किसी भी व्यक्ति के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करें, भारत में धर्म और राजनीति को एक दूसरे से अलग तथा पृथक् रखने की हमेशा कोशिश की गई है। भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, यहां राज्य की नजर में सब एक समान है। भारत में धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों को समानता का दर्जा प्रदान किया गया है। सभी धर्मों के नागरिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सभी धर्मों के नागरिकों को समान आदर व इज्जत से व्यवहार करें। भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य के सभी धर्मों को विकास का समान अवसर देती है, इस प्रकार यह माना जा सकता है कि धर्मनिरपेक्षता सर्वधर्म समभाव पर विशेष महत्व देकर उस पर केंद्रित करती है। धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत तर्क और विवेक की प्रधानता होती है, सभी व्यक्ति को सब कुछ कहने और विचार करने की स्वतंत्रता होने के साथ-साथ वैज्ञानिक आधिकारों को भी पूर्ण अधिकार के साथ प्रोत्साहित भी किया जाता है। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता से विविधता में एकता को बल मिलता है। हालांकि कुछ राजनीतिक दलों ने समय-समय पर भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सत्ता प्राप्त करने हेतु कमजोर करने की कोशिश की है, यह हमारी

जिम्मेदारी तो है ही साथ ही आम जनता, राजनीतिक दलों, मीडिया एवं सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की महती जिम्मेदारी है कि भारतीय संविधान के अनुरूप धर्मनिरपेक्षता का राजनीतिक, सामाजिक जीवन में पालन करें, जिससे हमारे देश का लोकतंत्र और अधिक सुदृढ़ होकर विश्व के लिए एक आदर्श प्रतिमान प्रस्तुत करें। आजादी के पूर्व तथा आजादी के पश्चात महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री आदि नेताओं का धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के प्रति अटूट श्रद्धा एवं विश्वास थास्थ स्वतंत्रता के पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन से पहले ही सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने धर्मनिरपेक्षता का मार्ग प्रशस्त कर दिया था, और स्वतंत्रता के बाद भारत में धर्मनिरपेक्षता की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई गई है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति को समानता स्वतंत्रता व न्याय जैसे मानव अधिकार प्राप्त हैं। और इन अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता को माना गया है, इसके अभाव में राज्य में समानता व धर्म निरपेक्षता की स्थापना नहीं की जा सकती है। भारत की सबसे बड़ी विशेषता विविधता में एकता ही रही है, विविधता में एकता का मूल मंत्र ही धर्मनिरपेक्षता का है।

